भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2709
मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

डेयरी सहकार योजना

†2709. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डेयरी सहकार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी डेयरी सहकारी समितियों को सहायता दी गई है; और
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई डेयरी सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है, का अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जो डेयरी सहकारी समितियों की अवसंरचना के निर्माण के साथ-साथ व्यावसायिक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से देश भर में डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करता है । देश में राज्य/बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी संस्था, डेयरी से संबंधित कार्यकलापों को शुरू करने के लिए अपनी उप-विधियों में उपयुक्त उपबंध के साथ, एनसीडीसी के दिशानिर्देशों और डवटेल्ड योजना(ओं) को पूरा करने के अधीन डेयरी सहकार के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। एनसीडीसी सहायता प्राप्त आवेदनों की विधिवत जांच के बाद लाभार्थी डेयरी सहकारी समितियों को सीधे या संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

(ख) एनसीडीसी ने डेयरी सहकार के तहत 19,938 डेयरी सहकारी समितियों को कुल 186.48 करोड़ रुपये (31.10.2021 से 08.12.2025तक) की कुल वित्तीय सहायता संवितरित की है, जिसका राज्य-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

क्रम.सं.	राज्य	लाभार्थी समितियों की संख्या	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	गुजरात	9472	49.81
2	उत्तराखंड	2766	23.49
3	बिहार	1409	9.72
4	महाराष्ट्र	1491	1.80
5	ओडिशा	943	0.81
6	तमिलनाडु	175	37.33
7	तेलंगाना	3018	51.93
8	राजस्थान	663	6.19
9	केरल	1	5.40
कुल		19938	186.48

(ग): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC) प्रस्तावों की प्राप्ति और योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता संस्वीकृत करता है । चूंकि डेयरी सहकार योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।